

श्रीलंकाई नौसेना ने चार भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, अवैध रूप से मछली पकड़ने का लगाया आरोप

नई दिल्ली, 18 जून 2024।

श्रीलंका नौसेना ने मगलबाह को चार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। नौसेना ने उन पर अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप लगाया है।

इस तरह के आरोपों में इस साल अब तक 180 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

द्वीप राष्ट्र की नौसेना ने एक बयान में कहा कि जागीरा प्राप्तियों के डेरेस्ट के उत्तरी द्वीप में आज

कथित तौर पर अवैध शिकार की ताजा घटना में एक भारतीय नौका जब की गई और चार मछुआरों को गिरफ्तार किया गया।

नौसेना ने कहा कि श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप लगाया है।

इस तरह के आरोपों में इस साल अब तक 180 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।



पुतिन 24 वर्षों में पहली बार उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे

मास्को, 18 जून 2024। 24 वर्षों में प्योग्यांग की अपनी पहली यात्रा से पहले, रूसी राष्ट्रपति ल्यादिमी पुतिन ने यूके ने मास्को के युद्ध का दृढ़ता से समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया के किम जॉन-उन शासन की प्रशंसा की है।



पुतिन के मगलबाह को किम से मिलने के लिए योग्यांग पहुंचने की उमीद है।

दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात सिंतंबर में रूस के सुदूर पूर्व में वोस्टोचनो कॉस्मोज़ेम में हुई थी, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 2000 के बाद से पुतिन की यह पहली यात्रा थार्यांग यात्रा है।

उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया में प्रकाशित एक पत्र में, पुतिन ने प्योग्यांग के साथ व्यापार और सुरक्षा प्रायोली के बाबत राजनीति का वादा योग्यांग के विपक्ष रोड़ाग सिन्हाता में छेंगे लेख में अभियोगीकी दबाव, लेकिन मेल और सैन्य धमाकों के बाबजूद अपने हिंदों की स्थानों के लिए योग्यांग के प्रयासों का समर्थन करने की भी कसम थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि दोनों देश परियोगी दोस्तों की उत्तरवाचकांशों का दृढ़ता से विश्व रुप से प्रवेश करना जारी रखेगे, जो न्याय के लिए प्रत्येक समाज पर आधारत बहुकालीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में बाधा उत्पन्न करती है।

पूर्व पीएम थकसिन शिनावात्रा जमानत पर रिहा, शाही परिवार को बदनाम करने का है आरोप

थाईलैंड, 18 जून 2024।

थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनावात्रा को 2015 के एक साक्षात्कार के द्वारा जी गई टिप्पणियों से जुड़े मामले में अभियोग चलाने के बाद 500,000 बात की जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दात्रप्रसाद आज केस चलाने के लिए मौजूद होने पर उन्हें जमानत मिलती है। उन्होंने कहा है कि उनका शारीरिक कार्य के शर्तों में संतुष्ट है।



थाईलैंड की राजशाही को बदनाम करने का आरोप

पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनावात्रा पर थाईलैंड की राजशाही को बदनाम करने के आरोप में मंगलबाह को औपचारिक रूप से केस दर्ज कराया गया है। जो देश की

यात्रावालों में एक है।

थाईलैंड में लेसे मैजेस्टे
का बढ़ रहा इस्तेमाल

थाईलैंड में राजतंत्र को बदनाम करने के लिए बनाए गए कानून के तहत किसी भी शख को तीन से 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस कानून को लेसे मैजेस्टे के नाम से जाना जाता है और वे दुनिया के इस तरह के सबसे कठोर कानूनों में से एक हैं। फिलहाल थाईलैंड में सरकार के आलोचकों को सजा देने के लिए इस कानून का इस्तेमाल काफी बढ़ रहा है।

18 साल पहले थाईलैंड की राजनीति से बेदखल किए पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनावात्रा आज भी देश में एक प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती है।

18 साल पहले थाईलैंड की राजनीति से बेदखल किए पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनावात्रा आज भी देश में एक प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती है।

जिसके तहत इस सीजन में लगभग

शीर्ष अदालत का लैंगिक समानता विधेयक के खिलाफ फैसला, राष्ट्रपति ने रखा चयन समिति के गठन का प्रस्ताव

कोलंबो, 18 जून 2024।

श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता विधेयक के खिलाफ फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लैंगिक समानता विधेयक की व्यापक समिधान के अनुच्छेद 12 के साथ मेल नहीं खाता। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति राजनीतिक मिशन को फैसले पर गौर करने के लिए एक चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। लैंगिक समानता विधेयक का उद्देश्य श्रीलंका में समानता के लिए एक चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। लैंगिक समानता विधेयक का उद्देश्य श्रीलंका में समानता के लिए एक चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है।



संवेदनशीलता को नुकसान पहुंच सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यह दलील भी दी कि यह विधेयक समलैंगिक विवाह की अनुमति देगा। इसके बाद श्रीराजनीति के लिए समान अनुमति देने वाली समीक्षाकारी और साक्षितक रूप से गलत होगा।

अदालत में लैंगिक समानता विधेयक के खिलाफ याचिकारी और अदालत की भी कसम थी। इनमें तर्क दिया गया था कि अगर विधेयक को अपनान के लिए संसद के दो-तीव्रांति सदस्यों की सांस्कृतिक

गई है। पिछले साल 2023 में 240 से 245 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस तरह की ज्यादातर घटनाएँ पाक जलडमरुमध्य में होती हैं। यह तमिलनाडु से उत्तरी श्रीलंका के बीच एक पक्ष है। यह मछलीयों के लिए समुद्र धरा माना जाता है।

श्रीलंका के मत्स्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मछुआरों का मुद्रा एक विवादास्पद मुद्रा है। श्रीलंका के बीच एक पक्ष है। यह मछलीयों के लिए समुद्र धरा माना जाता है। श्रीलंका के लिए एक चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है।

भारतीय मूल के डॉक्टर मेनन को मिला ब्रिटेन का प्रतिष्ठित CBE पुरस्कार



इसके बाद कैबिनेट में एडेनब्लक के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) शिक्षण अस्पताल में न्यूरोसाइंसेज क्रिटिकल केयर चॉन्ट (न्यूरोसाइंस) की स्थापना की। प्रोफेसर मेनन ने इस समान विशेषज्ञ (ब्रैन ट्रॉम्प एक्सपर्ट) और भारतीय मूल के मास्ट्रेक आजात के लिए ब्रिटेन के लिए नामांकित होने पर सम्मानित महसूस कर रहा है। मैं उन सभी की तरफ से इस समान को स्वीकार करता हूं, जिसने मेरे साथ काम किया।

**दिल्ली में हुआ था प्रोफेसर
मेनन का पालन-पोषण**

डॉक्टर डेविड कॉर्टन (सीयूच) एनएचएस फॉर्मर डेविल डेविड कॉर्टन के लिए दिया गया था। प्रोफेसर डेविल कॉर्टन के लिए विश्ववादालय में एनसीसीसिया के प्रोफेसर डेविड कॉर्टन के लिए विश्ववादालय में प्रमुख हैं। उन्हें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार 'कॉमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' (सीबीई) से सम्मानित किया गया।

**मैं सम्मानित महसूस कर
रहा हूं प्रोफेसर मेनन**

प्रोफेसर मेनन ने पुड़ुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं सायंस के प्रमुख हैं। उन्हें पुरस्कार 'कॉमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' (सीबीई) से सम्मानित किया गया।

कैबिनेट के अधिकारी ने दिया गया

फॉरेस्टर डेविल कॉर्टन के लिए एक चयन समिति ने संसद में अदालत के लिए फैसले पर समान उठाते हुए कहा कि अदालत का यह विधेयक समानता विधेयक को एक चुनौती देता है। उन्होंने संसद में अदालत के लिए फैसले पर गौर करने के लिए एक चयन समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इस चयन समिति को लेकर दिया कि यह विधेयक को अपनान के लिए संसद में अदालत के लिए फैसले पर गौर करने के लिए एक चयन समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा है।

फॉरेस्टर डेविल कॉर्टन के लिए एक चयन समिति ने संसद में अदालत के लिए फैसले पर गौर करने के लिए एक चयन समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इसके लिए एक चयन समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इसके लिए एक चयन समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इसके लिए एक चयन समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इसके लिए एक चयन समिति को गठित करने का प्रस्ताव रखा है।

कैबिनेट के अधिकारी ने दिया गया

क्या गेज बांध मुआवजा प्रकरण में फिर शुरू हुई दलाली ?

क्या अंकिता सोम के मार्गदर्शन में ही हो रहा है मुआवजे की राशि का वितरण?

पहले थे कांग्रेस से जुड़े दलाल अब भाजपाई दलाल सक्रिय

गेज बांध मुआवजा प्रकरण मामला एक गंभीर विषय बन चुका है, इसमें खेल चल रहा है खेल अधिकारियों के द्वारा ही खेला जा रहा है पूरा सेटिंग दलाल के द्वारा किया जा रहा है। किन भू स्थानियों के लालों में राशि मिलनी थी 30 साल से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। अब यह 80 के जगह 40 ही मिल रहा है तो उसमें भू स्थानी भी खुश है कुछ तो मिला। बहुत बड़ा सवाल है कि पहले या कहाँ कि भू स्थान सरकार के कार्यकाल में इस प्रकरण में कांग्रेसी दलाल लगे हुए थे अब सरकार बदलने के बाद भाजपाई दलाल सक्रिय हो गए हैं। जो भाजपाई गेज बांध मुआवजा प्रकरण पर साल भर पहले आरोप लगा रहे थे वहीं अब इस प्रकरण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं जैसा कि सूत्रों का कहना है।

मुआवजा के लिए 12 करोड़ आया, 2.5 करोड़ निकला: सूत्र

गेज बांध का प्रकरण 30 साल पुराना है लेकिन इस प्रकरण की राशि अपनी प्राप्त हुई है, सूत्रों का कहना है कि शासन द्वारा लगभग 12 करोड़ भेजा गया है जिसमें से जिम्मेदार अधिकारी द्वारा तकलीफ ही 2.5 करोड़ की राशि आहारण कर ली गई है अब उसे चेक के माध्यम से प्रभावितों को देने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रकरण में कई कठिनाएँ के नाम बदल जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है। नजायज पट्टा लेकर भी लोग मुआवजा राशि प्राप्त करने की जड़ी जहांद में हैं।

किस अधिकारी के साथ हुई थी दलाल की बैठक ?

मुआवजा प्रकरण में अब जो दलाल किस का व्यक्ति सक्रिय है वह भाजपा के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से गहरा संबंध रखता है ऐसा सूत्रों का कहना है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि जो दलाल सक्रिय है वह अधिकारी से संबंधित है और अधिकारी को एक जनप्रतिनिधि ने ही बैठक एवं अन्य कार्यों के लिए कहा था। दलाल को शुरू से हाराम की खाने की आदत है और वह दलाली करके ही ऐसों आराम की जिंदगी जी रहा है। सूत्रों का कहना है इसी जून माह में दलाल और एक अधिकारी की बैठक शहर के एक होटल में हुई थी दलाल वहां पहले से मौजूद था जबकि अधिकारी कुछ देरे बाद दलाल ने खासी राशि दिलाने की बात कह रहा है और प्राप्त राशि में से आधी राशि देने की बात कह कर रहा है। अब चूक भू स्थानीय पिछले 30 साल से परेशन हैं उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है अब जो मिल जाए वही सही है। इसलिए भू स्थानीय भी माफिया के जांसें में आ जा रहे हैं। क्षेत्र में बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों हैं जो कि जनता के लिए काम करने का ढोंग करते हैं इस मामले में उनकी चुप्पी है जो कि गंभीर मामला है।

क्या मुआवजा वितरण के लिए ही नहीं हटाई गई एसडीएम ?

गेज बांध मुआवजा वितरण का सारा काम बैकूंथपुर एसडीएम अंकिता सोम के नेतृत्व में किया जा रहा है, उनके द्वारा ही 2.5 करोड़ आहारण कर लेने की बात सूत्रों के द्वारा की जा रही है। ऐसडीएम अंकिता सोम को जब बैकूंथपुर का एसडीएम बनाया गया तो उसमें कांग्रेस सरकार के नेताओं की अहम भूमिका थी उस दौरान विपक्ष में रहे भाजपाईयों की एक नहीं सुनी जाती थी लेकिन सत्ता बदलते ही ऐसडीएम के सुर भी बदल गए हैं। जो भाजपाई एसडीएम के विरुद्ध आवाज उठाते थे वहीं अब ऐसडीएम की तारिक कर रहे हैं। जिले में अनेक डिटी कलेक्टर हैं जिन्हें ऐसडीएम बनाया जा सकता है लेकिन कोरिया कलेक्टर की क्या मजबूरी है कि अंकिता सोम को बैकूंथपुर से नहीं हटाया जा रहा है वह समझ दें परे है।

प्रमोशन के बाद एसडीएम बने रहना कितना सही ?

बतलाया जाता है कि जब अंकिता सोम को बैकूंथपुर का एसडीएम बनाया गया था तो इसमें तात्कालिक विधायक अधिकारी सिंहदेव की नियमांग करने का प्रस्ताव 1991 में तैयार हुआ, जिसमें लिए गए नियमों की भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यह प्रक्रिया 1992 में पूरी कर ली गयी। उस समय इस बांध को बनाने के लिये किसानों की 95 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण की भूमि में 49 हितग्राहियों के नाम शामिल थे जिन्हें तकरीबन 10.66 लाख भुगतान होना था जो तात्कालिक समस्याओं की वजह से अधिकारियों ने नहीं कर पाया और यह प्रकरण 26 साल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और जब शासन-प्रशासन जागी तो इस प्रकरण को आगे बढ़ाने की बाजाये नया प्रकरण शुरू कर दिया, इस 26 सालों में बाया भाजपा क्या क्रियाएँ समाप्ती आये और यह पर किसानों के अधिग्रहण के पैसों की चिंता किसी ने नहीं की। किसान भी एक समय के लिये इस पैसों को भूल बैठे थे पर कुछ जनप्रतिनिधि अपने निजी लाभ और अधिकारियों को प्रोतों बदलने के 2018 में कुछ भू-माफियाओं वे साथ मिलकर प्रकरण शुरू कराया पर सवाल यह है कि पुराने प्रकरण को दफन कर नये प्रकरण क्यों शुरू किया गया?

1992 का प्रकरण कैसे हुआ था

अधिकारित मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले के बैकूंथपुर के छरछ ग्राम में किसानों की भूमि की सिंचाई के लिये गेज नदी पर गेज बांध का निर्माण करने का प्रस्ताव 1991 में तैयार हुआ, जिसमें लिए गए नियमों की भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यह प्रक्रिया 1992 में पूरी कर ली गयी। उस समय इस बांध को बनाने के लिये किसानों की 95 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण की भूमि में 49 हितग्राहियों के नाम शामिल थे जिन्हें तकरीबन 10.66 लाख भुगतान होना था जो तात्कालिक समस्याओं की वजह से अधिकारियों ने नहीं कर पाया और यह प्रकरण 26 साल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और जब शासन-प्रशासन जागी तो इस प्रकरण को आगे बढ़ाने की बाजाये नया प्रकरण शुरू कर दिया, इस 26 सालों में बाया भाजपा क्या क्रियाएँ समाप्ती आये और यह पर किसानों के अधिग्रहण के पैसों की चिंता किसी ने नहीं की। किसान भी एक समय के लिये इस पैसों को भूल बैठे थे पर कुछ जनप्रतिनिधि अपने निजी लाभ और अधिकारियों को प्रोतों बदलने के 2018 में कुछ भू-माफियाओं वे साथ मिलकर प्रकरण शुरू कराया पर सवाल यह है कि पुराने प्रकरण को दफन कर नये प्रकरण क्यों शुरू किया गया?

बिना भौतिक सत्यापन के 21 हितग्राहियों

को मुआवजा राशि देने का मामला

21 हितग्राहियों में 4 करोड़ 75 लाख की राशि तो बंट गयी सवाल यह है कि जब यह पूरा मामले ही संदेह के थेरे में हैं तो इन्हीं हड्डबड़ी क्यों प्रशासन ने दिखायी राशि के भूतान करने में हालांकि राशि किया हितग्राहियों में बटा पर इसमें भी एक हड्डबड़ी दिखी जो हल्का प्रतवारी बिना भौतिक सत्यापन की चेक का वितरण करते हुए राशि दे दी गयी।

पहले थे कांग्रेस से जुड़े दलाल अब भाजपाई दलाल सक्रिय

अब भाजपाई दलाल सक्रिय सूत्र

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

शहर के एक होटल में दलाल के साथ

किस अधिकारी की हुई मीटिंग

दलाल के लिए किस जनप्रतिनिधि

ने किया था अधिकारी को फोन

शासन ने गेज बांध मुआवजा के लिए भेजे 12

करोड़ 2.5 करोड़ की निकासी भी हो चुकी

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठाया गया है?

कोरिया जिले में प्रशासनिक अव्यवस्था चरम सीमा पर, अधिकारी अपर कलेक्टर बनने के बाद भी अंकिता सोम को एसडीएम पद पर दर्या बैठ

